

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:—347/2013/225 (2013/00004)

1. गोपाल पुत्र श्रीचन्द,
 2. गणपत पुत्र श्रीचन्द,
 3. गुमान पुत्र श्रीचन्द,
 4. श्रीकरण पुत्र गणपत,
 5. करतार पुत्र गणपत,
 6. अवतार पुत्र गणपत,
- समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चाट, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोंडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 29.8.2013 अंतर्गत प्रकरण संख्या 61/2013.

उपस्थित:—

1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांक:— 24.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 29.8.2013 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरुद्ध अप्रार्थीगण/अपीलांटस के प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण/अपीलांटस की पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजियात खाता संख्या 1/1 के खसरा नंबर 1336 रकबा 6.46 मे से 5.0 है0, खसरा नंबर 835 रकबा 0.64 है0, खसरा नंबर 836 रकबा 1.10 है0 एवं खसरा नंबर 1169 रकबा 3.16 है0 भूमियां ग्राम चाट, तहसील नसीराबाद में स्थित है । उपरोक्त आराजियात पर प्रार्थीगण पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चले आ रहे है । तहसीलदार द्वारा प्रार्थीगण के विरुद्ध समय-समय पर धारा 91 एल0आर0एक्ट की कार्यवाही की जाकर शास्ति वसूल की गई है । प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के खातेदारी इंड्राज हेतु प्रार्थना पत्र राजस्व शिविर कैम्प भटियानी में पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी ने नियमानुसार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा ग्राम

पंचायत भटियानी द्वारा भी उक्त भूमि को खातेदारी इंद्राज हेतु अनापत्ति जाहिर की । प्रार्थीगण का विवादित आराजियात पर 100 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अप्रार्थी प्रार्थीगण को विवादित आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी०न्याया० ने दिनांक 29.8.2013 को प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये । अधी०न्याया० के इस आदेश के विरुद्ध अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी०न्याया० का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।
4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात पर अपीलांटस का पुश्तैनी समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । समय-समय पर तहसीलदार द्वारा अपीलांटस के विरुद्ध धारा 91 एल०आर०एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर शास्ति भी वसूली गई है जिससे अपीलांटस के कब्जे काश्त की पुष्टि होती है । प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि के खातेदारी इंद्राज हेतु प्रार्थना पत्र राजस्व शिविर कैम्प भटियानी में पेश किया । उक्त प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी ने नियमानुसार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा ग्राम पंचायत भटियानी द्वारा भी उक्त भूमि को खातेदारी इंद्राज हेतु अनापत्ति जाहिर की । प्रार्थीगण का विवादित आराजियात पर 100 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु अप्रार्थी प्रार्थीगण को विवादित आराजियात से बेदखल करने पर आमादा है । प्रार्थीगण द्वारा अधी०न्याया० के समक्ष विवादित आराजियात की खातेदारी बाबत अपीलांटस का वाद विचाराधीन है यदि उसके विचाराधीन रहते अप्रार्थी द्वारा अपीलांटस को विवादित आराजियात से बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलांटस द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा तथा अपूर्ण्य क्षति अपीलांटस को ही होगी । अधी०न्याया० को वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन अपीलांटस के पक्ष में निहित होने के बावजूद अधी०न्याया० ने अंतरिम निषेधाज्ञा पारित नहीं कर विधिक त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी०न्याया० का आदेश निरस्त किया जावे तथा ताफैसला वाद अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।
5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्प० संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी०न्याया० द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये हैं जो किसी आदेश की श्रेणी में नहीं आता है बल्कि विधिक प्रक्रिया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को पाबंद करने से पूर्व उसे सुना जाना आवश्यक है । अधी०न्याया० ने इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अप्रार्थी को नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये हैं । अधी०न्याया० द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश नहीं होने से अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है । बहस में यह भी कथन किया कि विवादित आराजियात सिवायचक भूमियां हैं जिस पर अपीलांटस ने पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है । नियमानुसार पुराने कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी दिये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांटस द्वारा अधीन्याया के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 212 राजकाशतअधि पेश किये जाने पर अधीन्याया ने दिनांक 29.8.2013 को प्रार्थीगण को सुनकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किये जाने के आदेश पारित किये है जो आदेश की श्रेणी में न होकर विधिक प्रक्रिया है । माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की फुल बैंच द्वारा रिवीजन/एलआर/9867/2012/नागौर बउनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम वगै में पारित निर्णय दिनांक 12.3.2014 में गार्ड लाईन की क्रम संख्या 2 में स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिये गये है कि:- “
The Appellate Courts have no jurisdiction to entertain appeals against such ad-interim ex-parte orders which are effective only till next date of hearing and have been passed under Rule 3 and 3 A of Order 39 of the Code or where there is no order of the trial court on the application of temporary injunction or appointment of receiver.”
7. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अधीन्याया द्वारा पारित आदेश अंतिम आदेश न होकर अंतरिम आदेश होकर विधिक प्रक्रिया है जिसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील यद्यपि संधारण योग्य नहीं है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है प्रार्थना पत्र धारा 212 राजकाशतअधि अधीन्याया के समक्ष विचाराधीन है । हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक मितव्यता को ध्यान में रखते हुए अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण अधीन्याया को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र धारा 212 राजकाशतअधि 1955 को उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर आवश्यक रूप से एक माह में निर्णित करे ।
8. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की है । प्रकरण अधीन्याया उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राजकाशतअधि का आवश्यक रूप से एक माह में निस्तारण करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी,